मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

दुष्यंत साफ-साफ बताओ	3
राफेल में झूठ किसने बोला	4
नहीं रुक रही किसानों की आत्महत्या	5
चौराहे पर मोदी	6
डॉक्टर नहीं रहा भगवान	8

वर्ष 33 अंक -5 फ़रीदाबाद 16-22 दिसम्बर 2018 फोन : - 9999595632 ₹2.50

निगमायुक्त मोहम्मद शाइन के हाथ हैं काले!

ठेकेदार से कमीशन लेकर बंद खाते का चैक दिया, तबादले पर 30 फाइलें चुरा ले गये

फ़रीदाबाद (म.मो.) अपने ग्यारह माह के कार्यकाल में बतौर निगमायुक्त मोहम्मद शाइन ने खट्टर सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा के दावे की कितनी धज्जियां उड़ाई, यह विस्तृत जांच का विषय है। फिलहाल उनके द्वारा किये गये दो आपराधिक घोटाले तो बिल्कुल नंगे होकर नाच रहे हैं।

इसी दिसम्बर में चार्ज छोड़ने से पहले उन्होंने एक ठेकेदार से कमीशन तो पूरा ठोककर वसूला और बदले में पेमेंट का जो चैक दिया वह बैंक ने लौटा दिया क्योंकि वह खाता काफी समय पहले बंद हो चुका था। अब ठेकेदार कभी नगर निगम के चक्कर काट रहा है तो कभी गुड़गांव में तैनात शाइन साहब के, कोई उसकी सुनने वाला नहीं।

मीडिया में बैठे चारण-भाट शाइन की

चोर के लिए मीडिया मचाये शोर

प्रशंसा के कसीदे गाते हुए बता रहे हैं कि वे इतने ईमानदार और सख्त प्रशासक थे कि स्थानीय राजनेताओं को रास नहीं आये। वे उनकी कोई परवाह नहीं करते थे, सब काम अपनी मनमर्जी से किया करते थे।

बात में कुछ सच्चाई हो भी सकती है क्योंकि नेता कौन से भले हैं, वे कौन से सही काम के लिए दबाव डालते हैं। परन्तु निगमायुक्त की सख्ती केवल लूट के माल में से अधिकतम वसूली तक ही सीमित थी। पुलिस मे एफआईआर दर्ज कराने और बीते वर्षो का आडिट कराने का नाटक केवल लूट कमाई कर चुके अफसरों से वसूली करने तक ही सीमित था। अपने पूरे कार्यकाल में न तो वे किसी भ्रष्टाचारी को गिरफ्तार करा सके और न ही एक रुपये की रिकवरी किसी भ्रष्टाचारी से उगलवा सके।

जिन तीस फाईलों को वे अपने साथ ले गये बताते हैं और अब उनकी विजिलैंस जांच का हव्वा खड़ा कर रहे हैं, वह केवल भ्रष्टाचारियों की बांह मरोड़ कर वसूली करने तक का ही नाटक है। इस बाबत आइजी विजिलैंस गुड़गांव सुभाष यादव से मिली जानकारी के अनुसार, उन्होंने अभी तक विजिलैंस को न तो कोई फाईल सौंपी है और न ही कोई पत्र लिखा है। जाहिर है जो-जो अधिकारी पैसे देता जायेगा अपनी-अपनी फाइल वापस लेता जायेगा। यह खुली ब्लैकमेलिंग नहीं तो और क्या है ?

कायदे से उन दोनों मामलों में शाइन के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिये क्योंकि फर्जी खाते का चैक देकर उन्होंने ठेकेदार के साथ धोखाधड़ी की है, परन्तु ठेकेदार ने तो यहीं ठेकेदारी करनी है उसकी क्या बिसात जो वह शिकायत भी कर सके। उसी तरह सरकारी फाईलों को अपने साथ ले जाना भी जुर्म है। इसके लिए उनके स्थान पर तैनात होने वाला अधिकारी मुकदमा दर्ज करा सकता है। परन्तु हमाम में सभी तो नंगे हैं, मुकदमा कौन दर्ज कराये ?

मजे की बात तो यह है कि इन सब काले कारनामों के बावजूद ईमानदार मुख्यमंत्री खट्टर शाइन पर इतने मेहरबान हैं कि उन्हें पदोन्नत करके गुड़गांव का मंडल आयुक्त बना दिया ताकि खुला खेल आगे भी खेल सकें। अंबाला में बतौर उपायुक्त वन विभाग का पैसा गबन करने में स्वयं की विजिलेंस जांच दबवाने वाले शाइन अब दूसरों को विजिलेंस जांच की धमकी दे रहे हैं।

राजीव गांधी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे राहुल

देश के लिए राहुल नरेंद्र मोदी से हर हाल में बेहतर रहेंगे, क्योंकि मोदी एकीकृत भारत का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकते, जो राहुल सहज ही कर लेंगे।

अब जब तीन विधानसभा में जीत ने कांग्रेसियों का विश्वास काफी हद तक लौटा दिया है, वे भी शायद सुनना चाहें कि उनके युवा अध्यक्ष राहुल गांधी अपने पिता राजीव गाँधी से बेहतर प्रधानमंत्री सिद्ध होंगे। अन्यथा यह बात मैंने इन वर्षों में जहाँ भी कही या लिखी है मुझे प्राय: उपहासपूर्ण चुप्पी का ही सामना करना पड़ा है। सत्ता से दूर रहने ने कांग्रेसियों को इस कदर उतावला और सत्ता से नजदीकी ने भाजपाइयों को इस कदर मतवाला कर दिया था!

राहुल गांधी की अच्छी किस्मत से उनके विश्वासपात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला अपनी-अपनी राजनीतिक उच्श्रृंखलता लेकर अभी तुरंत शासन के सेंटर स्टेज पर आने नहीं जा रहे हैं। यानी उन्हें अपनी स्वीकार्यता के कुछ और इम्तहानों से गुजरना ही होगा।

अचानक प्रधानमंत्री बना दिए गये पिता राजीव गांधी ने अरुण नेहरू, अरुण सिंह और मणिशंकर अय्यर जैसे असंयत और अनभिज्ञ दोस्तों को शासन सौंपने का खामियाजा भुगता था। कांग्रेस ने भी।

इस जीत के बाद अपनी पहली प्रेस कांफ्रेंस में राहुल ने किसान, युवा और छोटे व्यवसायी को अर्थव्यवस्था में लाभदायक भागीदारी के लिए चिन्हित किया है। श्रमिक उनके राडार से नदारद है। हालाँकि देर-सबेर वे जो भी मॉडल देंगे, और यह मॉडल महज 'सुशासन' ही नहीं हो सकता, उसमें श्रमिकों का सवाल भी शामिल होगा ही।

वक्त की पुकार कहिये कि इसी प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने 'भ्रष्टाचार' को भी एक बढ़ी राष्ट्रीय चिंता के रूप में चिन्हित किया है। अन्यथा, मुझे याद है, 2004 के संसदीय चुनाव की अप्रत्याशित विजय के आलोक में जयपुर में आयोजित एक चर्चा में इस सवाल को उन्होंने चेहरे से मक्खी की तरह उड़ा दिया था।

हालाँकि, 2018 में भी बदनाम कमलनाथ को ही मध्यप्रदेश की कमान सौंपी गयी है। यह भी स्पष्ट है कि इस मोर्चे पर राहुल अपने बहनोई रॉबर्ट वाड्रा या सहयोगी कॉर्पोरेट नवीन जिंदल जैसों को प्रशासनिक पहल का उदाहरण बनाने जैसा टेस्ट पास नहीं कर पायेंगे। तब भी गनीमत है कि लोकपाल जैसी हवाई युक्तियाँ या 'न खाऊंगा न खाने दूंगा' जैसे शेखचिल्ली जुमले उनके एजेंडे पर नहीं हैं।

फिर भी यदि मैं राहुल को राजीव से बेहतर प्रधानमंत्री होने की भविष्यवाणी कर रहा हूँ तो इसकी मुख्य वजह यह है कि वे गलतियों से 'सीख' कर प्रधानमंत्री बनेंगे न कि पिता की तरह प्रधानमंत्री बनकर गलतियाँ करने को स्वतंत्र होंगे। देश के लिए वे नरेंद्र मोदी से तो वे बेहतर रहेंगे ही क्योंकि मोदी एकीकृत भारत का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकते जो राहुल सहज ही कर लेंगे।

- पूर्व आईपीएस वीएन राय का विश्लेषण

एयर फ़ोर्स दायरे में बसे घरों का संकट सरकारी हरामखोरी व रिश्वतखोरी की देन

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्थानीय एयरफ़ोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में आज करीब 3000 घर आबाद हैं। इन्हें अवैध बता कर तोड़ने एवं हटाने का मामला गत कुछ वर्षों से चंडीगढ स्थित हाई कोर्ट में घिसट रहा है और वहां बसे लोग़ों की सांस अटकी हुई है। पहले यह दायरा 900 मीटर का था जो अब घटा कर 100 मीटर कर दिया गया है। इससे 800 मीटर के दायरे में आने वाले बीसियों हजार मकान मालिकों ने तो राहत की सांस ले ली परन्तु शेष बचे लोग़ों को अब संख्या कम रह जाने से खतरा अधिक महसूस होने लगा है।

विदित है कि शहर के पश्चिमी छोर पर डबुआ क्षेत्र के आसपास बसी इस घनी आबादी में मकानों का आकार 50 वर्ग गज से लेकर 150 वर्ग गज तक का ही है। बहुत कम मकान ही 200-250 वर्ग गज के हैं। समझा जा सकता है कि ये मकान समाज के सबसे कमजोर एवं मेहनतकश लोग़ों ने खून पसीने की कमाई से बनाये हैं। इन्होंने ये प्लॉट कोई अवैध रूप से नहीं कब्जाये हैं। बाकायदा भू-स्वामियों को कीमत का भुगतान करके सरकार को रजिस्ट्री शुल्क व तहसीलदार को रिश्वत देकर रजिस्ट्रियां कराई हैं।

सवाल यह पैदा होता है कि जब सत्तारूढ दल के छुटभैये नेता किसानों की जमीनों को बांध कर प्लॉटिंग करके जनता को बेच रहे थे और तहसीलदार बाकायदा रजिस्ट्री कर रहे थे उस वक्त सरकार कहां गयी थी ? उस वक्त क्या शासन-प्रशासन की आंखे फूट रही थी ? क्या उन्हें एयरफ़ोर्स स्टेशन का 900 मीटर वाला दायरा नहीं दिखाई दे रहा था ? गौरतलब बात यह भी है कि एयरफ़ोर्स अधिकारियों ने उस वक्त बाकायदा शासन-प्रशासन को पत्र लिखकर सूचित भी किया था; परन्तु भ्रष्ट राजनीतिक संरक्षण के चलते किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि जब एयरफ़ोर्स स्टेशन की उक्त परिधि-को सुरक्षा करणों से खाली ही रखना था तो राज्य अथवा केन्द्र सरकार ने उस परिधि-वाली ज़मीन का अधिग्रहण करके सार्वजनिक पार्क अथवा खेल के मैदान क्यों नहीं बनाये ? तत्कालीन सरकारों ने क्यों अवैध कॉलोनाइजरों को पनपने दिया और क्यों नहीं मज़दूरों के लिये, उनकी आवश्यकतानुसार आवासीय कॉलोनियों अथवा सेक्टरों का निर्माण किया ?

अब यदि सरकार जनविरोधी नहीं है तो क्यों नहीं इस स्टेशन को ही अरावली के उस संरक्षित वन्य क्षेत्र में स्थापित कर देती जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद लगातार फ़ार्म हाउस एवं रिसोर्ट बनाये जा रहे हैं ? उस क्षेत्र में एयरफ़ोर्स स्टेशन स्थापित करके वन्य क्षेत्र की सुरक्षा एवं उसमें अवैध निर्माणों को रोकने का काम भी एयर फ़ोर्स को ही सौंप दिया जाय तो अरावली का भी बचाव हो सकेगा। लेकिन निकम्मी एवं जनविरोधी सरकार कदापि ऐसा करने वाली नहीं क्योंकि फ़िर अरावली में अवैध कब्ज़ों एवं निर्माणों से होने वाली लूट कैसे हो पायेगी ?

मेवला महाराजपुर में अस्पताल के नाम पर 11 करोड़ हड़पने की तैयारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) बल्लबगढ़ के सेक्टर 3, फ़रीदाबाद के सेक्टर 30 व 55 में बने खड़े अस्पताल भवनों में डॉक्टर तो क्या पैरामेडिकल स्टाफ़ तक पर्याप्त नहीं हैं। यही हालत न केवल ज़िले भर के तमाम स्वास्थ्य केन्द्रों बल्कि राज्य भर के स्वास्थ्य केन्द्रों की है। ये चाहे शहरी क्षेत्रों में स्थित हों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में, हालत यह है कि इनमें एक साधारण प्रसव तक नहीं कराया जा सकता। सभी को दूर-दराज से चल कर ज़िले के मुख्य बीके अस्पताल में आना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यहां से भी दिल्ली के लिये रैफ़र कर दिया जाता है। इन हालात में साधन सम्पन्न लोग तो सरकारी के चक्कर में न पड़ कर सीधे प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं परन्तु ग़रीब लोग मजबूरन जान जोखिम में डाल कर सरकारी केन्द्रों पर आते हैं।

सरकार की हरामखोरी व रिश्वतखोरी का आलम यह है कि मौजूदा अस्पतालों एवं केन्द्रों की स्थिति को सुदृढ करने की बजाय नई-नई इमारतें खड़ी करने में लगी है। मानो डॉक्टरों व स्टाफ़ की बजाय इमारतें स्वत: ही मरीज़ों का उपचार कर देंगी। इसके पीछे पाखंडी सरकार की सोच यह है कि जब भी कोई इमारत बनेगी तो जनता में यह संदेश जायेगा कि सरकार उनके लिये कितना काम कर रही है, दूसरे इमारत की दर्शाई गयी लागत का एक बड़ा हिस्सा ठेकेदारों, अफ़सरों व नेताओं में बंट जाता है। इसी को तो कहते हैं हींग लगे न फ़िटकरी रंग आये चोखा।

इसके विपरीत जनता को यदि आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु मौजूदा अस्पतालों व केन्द्रों की व्यवस्था को सुदृढ करें तो नेताओं के पास उपलब्धियां गिनवाने व नारियल फ़ोड़ने को फ़िर क्या बचेगा ? लेकिन जनता आज इतनी भी

शेष पेज दो पर